Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 27 रायपुर, बुधवार 18 फरवरी 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

छत्तीसगढ़ सहित 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान

प्रदेश में 2 सीटों पर होगा चुनाव

16 मार्च को होगा मतदान

नई दिल्ली, 18 फरवरी (न्यूज चैनल)। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीख का एलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे। इनमें महाराष्ट्र की सात, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। वहीं ओडिशा की चार, तमिलनाडु की छह, असम की तीन, छत्तीसगढ़ की दो, हरियाणा की दो, तेलंगान की दो और हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है।

राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके मुताबिक 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च को नामांकन भरे जाएंगे और 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और 16 मार्च को ही वोटों की गिनती होगी। 20 मार्च 2026 से पहले चुनाव पूरा होना है। जिन दिग्गज नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, कनिमोझी, साकेत गोखले, उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर और अभिषेक मनु सिंघवी आदि शामिल हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को विधानसभा में अपनी मजबूत स्थिति का फायदा मिलेगा। वहीं तमिलनाडु और बंगाल में क्रमशः डीएमके और टीएमसी को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद हैं। हालांकि लेफ्ट के बंगाल में शून्य होने के बाद एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। बिहार में भाजपा गठबंधन की मजबूत स्थिति को देखते हुए यहां पांच में से चार सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस आगे रहेगी और हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर कड़ी टक्कर हो सकती है।

एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने दिग्गजों के भारत आगमन शुरू

फिनलैंड के प्रधानमंत्री पहुंचे भारत

नई दिल्ली, 18 फरवरी (न्यूज चैनल)। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो भारत दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वह इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेंगे। इस समिट में भाग लेने के लिए उनके आगमन पर कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो का हार्दिक स्वागत है। उन्होंने बताया कि यह दौरा भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगा, खासतौर पर डिजिटल, एआई, सतत विकास और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 फरवरी से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है, जिसमें दुनियाभर के नेता, नीति-निर्माता और टेक उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान वीआईपी मूवमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के चलते प्रतिनिधियों के लिए प्रवेश पर आंशिक प्रतिबंध रहेगा। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार और गुरुवार को सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन में शामिल होने वाले डेलिगेट्स को शाम 4:30 बजे तक कन्वेंशन एरिया खाली करना होगा, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद प्रधानमंत्री राज्य अतिथियों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे।

सीबीएसई दसवीं बोर्ड की परीक्षा शुरू 759 शामिल, 3 रहे अनुपस्थित

धमतरी, 18 फरवरी (हाईवे चैनल)। सीबीएसई दसवीं बोर्ड की परीक्षा मंगलवार से शुरु हो गई है। पहले दिन गणित का पर्चा हुआ। परीक्षा देकर निकले विकास कुमार, प्रांजल, अजय कुमार आदि ने बताया कि गणित के पर्चे में पूछे गये कुछ सवाल बेहद कठिन थे। इसे हल करने उनके अलावा अन्य छात्र-छात्राओं को भी खूब दिमागी कसरत करनी पड़ी।

जिले में उक्त परीक्षा मेनोनाइट इंग्लिश स्कूल व डीपीएस स्कूल एवं जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद में आयोजित हुआ। इसमें 762 में से 759 शामिल हुए। 3 अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक ली गई। आज बारहवी की परीक्षा शुरु हुई।

आज गरजेंगे मिग-29के, एलसीए तेजस और पी-8आई टोही विमान

राष्ट्रपति लेंगी अंतरराष्ट्रीय बेड़े की सलामी

नई दिल्ली, 18 फरवरी (न्यूज चैनल)।सिटी ऑफ डेस्टिनी कहे जाने वाले विशाखापत्तनम के समुद्री तट पर बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (आईएफआर) के जरिये दुनिया को भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का परिचय देंगी। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार शाम विशाखापत्तनम पहुंची। मुर्मू सुबह बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर समुद्र के बीच खड़े बेड़े का निरीक्षण करेंगी। इस रिव्यू में भारतीय नौसेना के साथ-साथ मित्र देशों के कुल 71 जहाज और पनडुब्बियां शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टर फ्लाई-पास्ट कर राष्ट्रपति को सलामी देंगे। आकाश में मिग-29के, एलसीए तेजस, पी-8आई टोही विमान और सी-किंग हेलिकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। दुनिया के सबसे घातक समुद्री कमांडो माने जाने वाले नौसेना के मार्कोस समुद्र के बीच विशेष युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी करेंगे।

गूगल प्रमुख सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 20 फरवरी को लेंगे भाग

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पिचाई भारत में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने आए हैं और 20 फरवरी को समिट में मुख्य भाषण देंगे। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर खुशी हो रही है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर खुशी हो रही है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हुए शामिल

तकनीक संचालित प्रशासन भविष्य की आवश्यकता- उपमुख्यमंत्री

रायपुर, 18 फरवरी (हाईवे चैनल)। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडियाङ्कएआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेकर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वे लीडर्स प्लेनरी सत्र में शामिल हुए और शासन-प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभावी उपयोग पर विशेष रुचि दिखाई। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सम्मेलन के दौरान एआई के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करने तथा डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करने के विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के सफल उपयोग के उदाहरणों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का द्वार भारत को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत द्वारा ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है, जिसमें अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय भागीदारी देखने को मिली है। 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, 60 मंत्रियों और 500 से अधिक वैश्विक एआई नेताओं की उपस्थिति इस आयोजन की महत्ता को दर्शाती है।

शर्मा ने बताया कि नीति-निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर यह सम्मेलन इंडियाएआई मिशन और डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत वैश्विक एआई विमर्श को ठोस एवं क्रियान्वयन योग्य विकास परिणामों में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने समिट के प्रति वैश्विक उत्साह को उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि 700 से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि पूरा विश्व भारत की एआई पहल को उत्साह से देख रहा है और सहयोग के लिए आगे आ रहा है। शर्मा ने कहा कि तकनीक संचालित प्रशासन ही भविष्य की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटल नवाचारों को अपनाकर सुशासन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए राज्य में एआई आधारित समाधान लागू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर सहयोग की संभावनाएं तलाशीं। उनका मानना है कि एआई का समुचित उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बना सकता है।

ब्रेकिंग न्यूज

भारत और नेपाल ने कानूनी सहायता समझौते पर किया हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 18 फरवरी (न्यूज चैनल)। भारत और नेपाल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस में दोनों देशों के सक्षम अधिकारियों को आपराधिक जांच और कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने में मदद मिलेगी। यह समझौता कई वर्षों की बातचीत के बाद हुआ है। पिछले साल जुलाई में नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की बैठक में सहमति बनी थी। हालांकि इसपर मंगलवार को काठमांडू में हस्ताक्षर किए गए। इससे वित्तीय और गैर-वित्तीय अपराधों के साथ-साथ आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया। कानून मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नेपाल के विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बिनोद कुमार भट्टराई और नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने विधि मंत्री अनिल कुमार सिन्हा और कई मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अपनी-अपनी सरकारों की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा, इससे आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य एकत्र करने और आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के सक्षम अधिकारियों के बीच सहयोग के लिए एक औपचारिक कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस समझौते से कानून के शासन को मजबूत करने और न्याय प्रशासन में संस्थागत समन्वय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। नेपाल में वित्तीय अपराधों को कम करने इसमें कहा गया है, इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के केंद्रीय अधिकारियों के बीच सहयोग और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

अस्पताल जा रहे पिता-पुत्र को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर मौत

रायगढ़, 18 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को पीछे से रौंद दिया। इस हादसे में पिता और उसके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। यह मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के पठान कॉलोनी निवासी मोहम्मद असरफ कुरैशी (32 वर्ष) मंगलवार सुबह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से रायगढ़ जिला अस्पताल जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे जब उनकी बाइक तराईमाल बंजारी मंदिर के पास स्थित फिरोज टायर दुकान के सामने पहुंची, तभी पीछे की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक ष्टस्न 04 स्न्न 9377 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोहम्मद असरफ कुरैशी और उनके 7 वर्षीय बेटे मोहम्मद अलताफ कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ धारा 281, 125(ए), 106(1) बीएनएस एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर दुर्घटनाकारी वाहन को कब्जे में ले लिया है। मामले की आगे की कार्रवाई जारी है।

'नाड़ा खोलना' अश्लील हरकत नहीं बलात्कार का प्रयास, हाईकोर्ट का आदेश रद्द

नई दिल्ली, 18 फरवरी (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादास्पद तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें एक नाबालिग के साथ हुई बर्बरता को महज अपराध की तैयारी बताया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने न केवल आरोपियों पर सख्त धाराएं बहाल की हैं, बल्कि निचली अदालतों के जजों को %कानून के साथ करुणा% का पाठ पढ़ाने का भी जिम्मा उठाया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

यह मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां एक नाबालिग लड़की को खींचकर पुलिया के नीचे ले जाने और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए रेप के प्रयास की धाराएं लगाई थीं, लेकिन मार्च 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कानूनी गलियारों और समाज में आक्रोश पैदा कर दिया। हाईकोर्ट का मानना था कि पायजामे का नाड़ा खोलना रेप का प्रयास नहीं बल्कि केवल गरिमा भंग करने जैसा कम गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को न्याय की भावना के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट के आदेश को कूड़ेदान में डाल दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी की। अदालत ने साफ किया कि किसी महिला के कपड़े उतारने की कोशिश करना सीधे तौर पर बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने जजों को आईना दिखाते हुए कहा कि यदि फैसले में पीड़िता की पीड़ा के प्रति सहानुभूति और तथ्यों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो वह न्याय नहीं है। बेंच के अनुसार, कानूनी सिद्धांतों का बोझ तब तक व्यर्थ है जब तक जज पीड़िता की लाचारी को महसूस न कर सकें। इस फैसले का असर केवल इस एक केस तक सीमित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के लिए एक बड़ा सुरक्षा तंत्र तैयार करने का आदेश दिया है। नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी के निदेशक को एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया गया है, जो जजों के लिए विशेष गाइडलाइंस तैयार करेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यौन अपराधों की सुनवाई के दौरान न्यायिक अधिकारी संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपराध की गंभीरता को समाज और पीड़िता के नजरिए से समझें।

तारिक रहमान के शपथ के बाद ही जमात ने दे दी बड़ी चेतावनी! कैबिनेट के शपथ ग्रहण का किया बहिष्कार

नई दिल्ली, 18 फरवरी (न्यूज चैनल)। बांग्लादेश में एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी देश का कार्यभार संभाल रही थी तो दूसरी तरफ चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जमात इस्लामी पहले दिन से ही आक्रामक मोड़ में आ गई। बांग्लादेश में जुलाई चार्टर को लेकर राजनीतिक संकट गहराता दिख रहा है। बीएनपी ने संविधान सुधार परिषद की सदस्यता के लिए शपथ लेने से इंकार कर दिया। जिसके बाद जमात और एनसीपी ने कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। दरअसल बीएनपी के सदस्यों ने सांसद के रूप में तो शपथ ले ली लेकिन उन्होंने जुलाई चार्टर से जुड़े संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने से इंकार कर दिया। इस बात से नाराज जमात इस्लामी और उसकी गठबंधन सहयोगी नेशनल सिटीजन पार्टी ने बीएनपी कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया।

12 फरवरी को हुए बांग्लादेश के चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी 212 सीटें जीतकर सत्ता में आई। जमात और एनसीपी समेत 11 गठबंधन सहयोगियों ने मिलकर 77 सीटों पर जीत दर्ज की। 12 फरवरी को चुनाव के साथ-साथ जुलाई चार्टर पर भी जनमत संग्रह कराया गया। जिसे 62त्न लोगों ने अपना समर्थन दिया। मंगलवार को बांग्लादेश में जीते हुए उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। जमात और एनसीपी चाहते थे कि जुलाई चार्टर के संबंध में भी एक शपथ ग्रहण हो। जुलाई चार्टर का मकसद बांग्लादेश की संसद को 180 दिनों के लिए संविधान सभा में बदलना है। जिससे नई संसद को बांग्लादेश के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में बदलाव करने का अधिकार मिल सके। बीएनपी ने अनक्षा के साथ जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन उसके नेताओं का कहना है कि चार्टर के कई प्रावधानों पर पार्टी को आपत्ति है।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, सुनेत्रा पवार अपने पति अजीत पवार की मौत की सीबीआई जांच की मांग रखी है।

चुहिया- हां जी, सीबीआई जांच तो हो जाएगी पर रिपोर्ट नहीं आएगी।